5जी के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाएगा प्रोत्साहन

उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई ही रामबाण, 30 लाख करोड़ का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का रामबाण चलाया है। इससे 30 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पीएलआई से 60 लाख लोगों को रोजगार की उम्मीद है।

प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिला है। इसी के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष की जाएगी। इसी के साथ 5जी नैटवर्क शुरू होने का रास्ता खुल जाएगा। वर्ष 2022 में 5 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी और 5जी नेटवर्क शुरू होने से विकास में तेजी आएगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए वैश्विक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के तहत वार्षिक संग्रह की 5 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी। इससे तकनीक और समाधानों का अनुसंधान एवं विकास और वाणिज्यीकरण बढ़ेगा।

स्टार्टअप के लिए एक साल बढ़ी टैक्स राहत

कोराना काल में दो साल से चुनौतियों से जूझ रहे स्टार्टअप को बड़ी राहत मिली है। उन्हें मिलने वाली टैक्स राहत की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है। यह टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक मिलेगी। पिछले कुछ सालों में देश में स्टार्टअप में कई गुना वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2022 तक नियमित स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले ही प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र थे।

■ अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहन की अवधि एक साल बढ़ाई गई है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है।

2025
तक भारत के हर गांव में बिछेगी ऑप्टिकल फाइबर

47
स्टार्टअप हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के इस साल

14000
से अधिक स्टार्टअप को 2021 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी

44 भरतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया

पूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये

सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन के बजट में 9.8 फीसदी की बढ़ोतरी कर 119696 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये में 2.33 लाख करोड़ रुपये वेतन व संगठनात्मक रखरखाव पर खर्च होंगे। 20100 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए रखे गए हैं। वहीं रक्षा खरीद के बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस पैसे से नए हथियार, हवाई जहाज, जंगी जहाज और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे।

-राजनाथ सिंह ● रक्षामंत्री

रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी कंपनियों व स्टार्टअप के लिए 25 फीसदी बजट रखना बेहद शानदार कदम है। इससे देश रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

घरेलू रक्षा उद्योग से होगी 68% खरीद निजी कंपनियां-डीआरडीओ आएंगे साथ

सेना के लिए उन्नत हथियारों का निर्माण अब देश में ही घरेलू कंपनियां करेंगी। सरकार रक्षा उपकरणों का आयात घटाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। 2022-23 में घरेलू रक्षा उद्योग से 68 फीसदी खरीद का लक्ष्य है। पिछले वर्ष यह 58 फीसदी था।

निजी कंपनियों को डीआरडीओ के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें एसपीवी मॉडल के तहत डीआरडीओ व विभिन्न संगठनों के साथ रक्षा उपकरण डिजाइन और मिलिट्री प्लेटफार्म के विकास पर

काम करने का मौका मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के रास्ते निजी कंपिनयों, स्टार्टअप के लिए खुलेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास के कुल बजट का 25 फीसदी रक्षा उद्योग की कंपिनयों व स्टार्टअप के रखा जाएगा।

25% अनुसंधान एवं विकास बजट निजी कंपनियों स्टार्टअप के लिए

टेस्टिंग व प्रमाणन के लिए विशेष नोडल संस्था बनेगी

उपकरणों की सटीकता की जांच व प्रमाणन के लिए एक विशेष नोडल संस्था बनेगी। यह हथियारों की गुणवत्ता परखने के बाद प्रमाणपत्र जारी करेगी।

■ **आधुनिकीकरण पर जोर :** रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आधुनिकीकरण पर जोर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन प्रणाली, जियोस्पेशियल सिस्टम विकसित होगा।